Regd. No. 185

Haryana College Teachers' Association

(Affiliated to AIFUCTO)
Website : ww.hcta.in

Dr. Narender Chahar
President
Vaish College, Bhiwani
Mob. : 098133-26900
Email: narenderchahar11@gamil.com

Dr. Ravinder Gasso
General Secretary
D.A.V. College, Pundri (Kaithal)
Mob. : 094161-10679
Email: gassoravinder@gamil.com

Ref. No.....

Dated 13/2/13

For Circulation Among Unit Members

आदरणीय दोस्तो !

13.01.2013 को दयाल सिंह कॉलेज करनाल में नवनिर्वाचित राज्य कार्यकारिणी की प्रथम मीटिंग में बड़ी संख्या में साथियों ने भाग लिया। मीटिंग के शानदार प्रबन्ध और आदर-सत्कार के लिए हम दयाल सिंह कॉलेज यूनिट का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। मीटिंग में 28 अक्तूबर 2012 के बाद की कार्यवाई की रिपोर्टिंग पर चर्चा की गई तथा निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-

1. पदाधिकारियों की 11.12.2012 को हुई मीटिंग में निम्न पदाधिकारियों के मनोनयन का कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदन किया गया।

1. डॉ इन्द्र सिंह (संगठन सचिव) एम जे के कॉलेज, कलानौर, रोहतक।
2. प्रो. एस एस ढिल्लो (संगठन सचिव) सी आर एम जाट कॉलेज हिसार।
3. प्रो. सज्जन सिंह (संगठन सचिव) जी एम एन कॉलेज अम्बाला कैंट।
4. प्रो. सुबे सिंह (संगठन सचिव) श्री गुरू हरि सिंह कॉलेज, श्री जीवन नगर, चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा जोन ।
5. डॉ यशवीर सिंह (प्रैस सचिव) जे वी एम जी आर आर कॉलेज, चरखी दादरी।
6. डॉ दलबीर सिंह (प्रैस सचिव) डी ए वी कॉलेज, सढौरा।

प्रो. अतर सिंह, सी आर एम जाट कॉलेज, हिसार तथा डॉ राजवीर पाराशर, आर के एस डी कॉलेज, कैथल विशेष आमन्त्रित पदाधिकारी होंगे।

2. डी ए वी कॉलेज पूण्डरी के निलम्बित प्राचार्य की बहाली का विरोध :

27.12.2012 को डी ए वी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी ने गवर्निंग बाडी की मीटिंग में निलम्बिल प्राचार्य डॉ सुभाष तंवर को जांच रिपोर्ट के आधार पर बहाल किया है। राज्य कार्यकारिणी जांच

रिपोर्ट व इस निर्णय पर अपना कड़ा एतराज प्रकट करते हुए डॉ तंवर के खिलाफ समुचित कार्यवाई की मांग करती है। डी ए वी कॉलेज पूण्डरी यूनिट ने इस सम्बन्धी एच सी टी ए के निर्देश पर विस्तृत ज्ञापन प्रबन्ध समिति को भेज दिया है। कार्यकारिणी ने इस मामले में संघर्ष जारी रखने का निणर्य लिया है और समयानुसार आगामी कार्यवाई के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत किया है। पदाधिकारी इस सम्बन्धी एक बार प्रबन्ध-समिति से मिल भी चुके हैं।

3. बकाया फीस

यूनिटों की बकाया फीस के बारे में वित्त सचिव डॉ राम पाल सिंह द्वारा तैयार लिस्ट भेजी जा रही है। यूनिटों से अनुरोध है कि वे तुरन्त **हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन** के नाम ड्राफ्ट बनाकर वित्त सचिव को गुरू नानक खालसा कॉलेज करनाल के पते पर भेजें। इसे अति आवश्यक समझा जाए।

4. सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज इतिहास और अनुभव

दोस्तों ! यह प्रोजेक्ट हमने अपने ऐडिड सिस्टम की प्रासंगिकता सिद्ध करने तथा इसे मजबूत बनाने के उद्देश्य से अपने हाथ में लिया है। इससे एकत्रित तमाम आंकड़े व तथ्य भविष्य के संघर्षों में हमारी सहायता करेंगे।

यह लगभग 500 पेज (दो खण्डों में) का अनुपम ग्रंथ बनेगा। प्रत्येक कॉलेज के लिए इसमें 2 से 5 पेज निर्धारित हैं। कॉलेज के प्रिंसीपल व यूनिट के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कॉलेज के इतिहास, उपलब्धियों, योगदान व वर्तमान सम्बन्धी 2 से 5 पेज में ही एक बढ़िया सम्पादित नोट ही भेजे। ज्यादा विस्तृत सामग्री का सम्पादन हमारे लिए संभव नहीं होगा।

स्टॉफ (टीचिंग, नॉन टीचिंग, प्राचार्य) के बारे में प्रोफार्मा अलग से भेजते हुए ध्यान रखें कि उसमें सबके फोन व ई मेल पते अवश्य हों। इस सामग्री को डायरेक्ट्री के रूप में अलग से प्रकाशित किया जाएगा।

(यह कार्य सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण है)

हिन्दी की सामग्री Kuruti Dev 10 में, अंग्रेजी की सामग्री Times New Roman Font तथा Pagemaker में ई मेल द्वारा ही भेजे।

20-21 फरवरी 2013 को 11 से 1 बजे तक कॉलेजों में धरना

दोस्तो ! ऑल इण्डिया फैण्डरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एण्ड कॉलेज टीचर्स ऑगेनाईजेशंस (ए-आई-फुक्टो) के निर्देशानुसार हमारी कार्यकारिणी ने दो दिवसीय राष्ट्र-व्यापी हड़ताल को समर्थन देने का निर्णय लिया है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लुधियाना में 10.02.2013 को हुई ए-आई-फुक्टो

की उत्तर क्षेत्रीय मीटिंग में इस सम्बन्धी निर्णय लिया गया कि सभी प्रदेशों के शिक्षक संगठनों द्वारा काले बिल्ले लगाकर कॉलेज/यूनिवर्सिटी कैम्पस में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक धरना दिया जाएगा।

यह विरोध प्रदर्शन केन्द्र सरकार की उच्च शिक्षा के प्रति नकारात्मक नीतियों के विरोध में किया जाएगा। इसमें मुख्य मांगे हैं :-

1. नई पैंशन सम्बन्धी (PFRDA) बिल वापिस लिया जाए तथा 2004 से पहले वाली पैंशन स्कीम लागू की जाए।
2. कॉलेजों व यूनिवर्सिटयों में शिक्षकों के सभी खाली पद स्थाई आधार पर तुरन्त भरे जाएं।
3. अस्थाई, अनुबन्ध या पार्ट टाईम शिक्षकों को नियमानुसार पूरा वेतन व सेवा शर्तें प्रदान की जाए।
4. शिक्षा का निर्लज्ज व्यापारीकरण बन्द किया जाए।
5. प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं पर समाजिक नियन्त्रण लागू किया जाए।
6. यू.जी.सी. अनॉमलि (अनियमितता सम्बन्धी) कमेटी की सिफारिशों को तुरन्त जारी किया जाए।
7. यू.जी.सी. वेतनमानों को सम्पूर्णता में (65 वर्ष पर सेवानिवृत्ति व कॉलेजों में प्रोफेसर-पद समेत) लागू किया जाए।
8. संसद में प्रस्तुत उच्च शिक्षा सम्बन्धी बिलों को वापिस लिया जाए। (बिलो सम्बन्धित विस्तृत जानकारी hcta.in पर उपलब्ध है।)

सभी यूनिटों से अनुरोध है कि इस कार्यवाही को पूरी तरह सफल बनाया जाए।

(डॉ रविन्द्र गासो)